epaper
हिन्दुस्तान

• आम बजट में आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा खर्च • डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कई बड़े ऐलान

सबके विकास पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट था। • एएनआई

02/02/2022

फीसदी का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम में दे सकेंगे राज्यों के भी कर्मचारी, पहले यह 10 था जबकि केंद्र के कर्मियों के लिए यह पहले से 14 है।एनपीएस में योगदान कर छूट दिलाता है।

• कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 कर दर को घटाकर 15 करने का ऐलान, सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया।

• व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जाएगा।

• उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। एक करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को अतिरिक्त कर्ज।

• 14 क्षेत्रों से शुरू हुई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ेगा, इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

• एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स में रोजगार की संभावनाएं। टास्क फोर्स बनाकर काम होगा।

• स्टार्टअप को कर में मिली छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी, इससे युवा स्टार्टअप के लिए प्रेरित होंगे।

• सभी राज्यों में कक्षा एक से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा।

• विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

कर्मचारी

14 फीसदी का योगदान नेशनल पे सकेंगे राज्यों के भी कर्मचारी, था जबकि केंद्र के कर्मियों के

लाख करोड़ का बजट पेश किया सीतारमण ने, पिछले साल से 4.61 लाख करोड़ ज्यादा

नई दिल्ली | सौरभ शुक्ल

कोरोना की तीसरी लहर से उबर रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने जा रही है ताकि रोजगार के मौके सृजित किए जाएं। इसी साल 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और 25000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 36 फीसदी ज्यादा रकम दी गई है। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में भी 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

वित्तमंत्री ने कारोबारियों को कुछ नए कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, सेवाओं के डिजिटल स्वरूप में विस्तार, महिलाओं के पोषण की व्यवस्था, मिशन मेक इन इंडिया के तहत नौकरियां, पीएलआई स्कीम में अतिरिक्त रकम और नई ट्रेनों का भी ऐलान किया। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ लाने की भी घोषणा की।

वित्तमंत्री ने कहा, 'हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 25 साल बाद हम 'इंडिया100' का जश्न मनाएंगे, यह बजट अगले 25 साल में अर्थव्यवस्था की बुनियाद तैयार करेगा।' मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं दिए जाने के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने दो साल से कोई कर नहीं बढ़ाया है। हमने कर बढ़ाकर पैसे जुटाने की कोशिश नहीं की। हम नहीं चाहते हैं कि महामारी के दौर में लोगों पर कर का बोझ बढ़े। बजट में किसानों-व्यापारियों पर खासा ध्यान दिया गया है।